Office of the Accountant General (A&E), Kerala,
P.B.No.5607, M.G.Road, Thiruvananthapuram-695039, Phone: 0471-2330311, Fax: 0471-2330242.

P19/II/DRSSA-142/Bihar/ **Dated:22/12/2017**

To

All District/Sub Treasury Officers

Sir,

Sub: Sanction of 268 % Dearness Allowance/Dearness Relief in the place of 264 % with effect from 01/07/2017 to Bihar State Government Servants/Pensioners and Family Pensioners receiving pension in Non-Revised Pay Scales as per the Fifth Pay Commission reg.

Ref: 1.SSA No.Pen-09/Seal/Authority No-35 dated 14/11/2017 of the Accountant General (A&E), Bihar, Patna.
2. Letter No.3 A-2-PR-(Allowance)-08/2013-8398/Fin dated: 25/10/2017 of Department of Finance, Government of Bihar.

I am to enclose herewith copies of Government orders issued by the Government of Bihar regarding Sanction of 268 % Dearness Allowance/Dearness Relief in the place of 264 % with effect from 01/07/2017 to Bihar State Government Servants/Pensioners and Family Pensioners receiving pension in Non-Revised Pay Scales as per the Fifth Pay Commission and SSA regarding the same issued by the Accountant General (A&E), Bihar, Patna, in the reference cited. The same is being placed in the official website of this office (www.agker.cag.gov.in). under the link "Treasury endorsement of orders for other states". A copy of this letter may be exhibited on the notice board of the treasury.

Yours faithfully

Sr. Accounts Officer

Copy to:-

The Director of Treasuries
Thiruvananthapuram

Sr. Accounts Officer

Speed Post

PM/2/472/2017-18

23/11/17

322814

21/11/17

P19/II/PSSA-142

18/12/17

/3363

6.12.17. PM

THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), BIHAR, PATNA

Pen-og Seal Authority No. 35

Dated 14.11.2017

Pr. Accountant General (A&E)

Kerala, Post Box No. 5607, M.G. Road,

Thiruvananthapuram - 695039

... of Dearness relief of State Government Pensioners,

... Govt. Resolution No.

(1) Increase of DR for Pensioners/F.P 4% to 5% w.e.f 1.7.2017

(2) " " " " " (Unrevised) 5th CPC 264% to 268% w.e.f 1.7.2017

(3) " " " " " (Unrevised) 6th CPC 136% to 139% w.e.f 1.7.2017

... forward herewith Hindi/English version of copies of Govt. of Bihar.

(4) Increase of Medical Allowance 200/ to 1000/ - w.e.f 20.10.17

...solution No. .... Dated .... for your needful action

... requested to circulate this order to all Treasuries/Sub Treasuries and

...anks in your Jurisdiction for necessary action.

...acknowledge the receipt of the same with enclosure

(1) संख्या-3-ए-2-वि०पु०-(मदा)-08/2013-8392/दि० 25.10.2017

(2) " " " " " " -8398/दि० 25.10.2017

(3) " of Bihar Govt. " " " " " -8399/दि० 30.10.2017

... No.

(4) संख्या-वि०(27)पे०को०-(पु०)22/2017 दिनांक 30.10.2017

Yours faithfully

Sr. Accounts Officer, Bihar, Patna

PM/2

22/11

To P19 section for n.a.

...-IX-Spl.-Bihar

Date

... for information and necessary action to:

... Secretary to the Govt. of Bihar, Finance Deptt., Patna

... Secretary, Bihar Pensioner Samaj, Vidya Vasini Sadan,

... Patna-800013.

... Office of E.A. Pension-I

Sr. Accounts Officer, Bihar, Patna

22/11

841

6/12/17

To,

Hindi cell

may please be translate in to English from page 3 to 10.

AAO

P19.

Pen-01(Gen) 73 - 847

संख्या-3ए-2-वे०पु०-(भत्ता)-08/2013-**8398**/वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक:-**25.10.2017**

विषयः- पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/ पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता/राहत की दरों में दिनांक-01/07/2017 के प्रभाव से 264 प्रतिशत के स्थान पर 268 प्रतिशत महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति।

31 OCT 2017

वित्त विभाग के संकल्प सं०-3168, दिनांक-05/05/2017 के द्वारा पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतन/पेंशन प्राप्त करने वाले राज्य कर्मियों को दिनांक-01/07/2016 के प्रभाव से 256 प्रतिशत तथा दिनांक-01/01/2017 के प्रभाव से 264 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति दी गयी थी।

2. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापांक-1(3)/2008-E-II(B), दिनांक-26/09/2017 द्वारा पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे केन्द्रीय कर्मियों (यानि जिनका वेतन पुनरीक्षण 01/01/2006 से नहीं हुआ है) को दिनांक 01/07/2017 के प्रभाव से मंहगाई भत्ता/राहत की पूर्व स्वीकृत दर 264 प्रतिशत को संशोधित करते हुए 268 प्रतिशत की स्वीकृति दी गई है ।

pen-01/GM 31/10

3. राज्य सरकार सामान्यतः अपने कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी पद पर एवं उसी तिथि से करती रही है ।

4. उक्त के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया जाता है कि-

(i) पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी दिनांक-01/07/2017 के प्रभाव से अपुनरीक्षित वेतन/पेंशन में 264 प्रतिशत के स्थान पर 268 प्रतिशत महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति प्रदान की जाय ।

(ii) दिनांक 01/01/2006 के पूर्व एवं दिनांक 01/01/1996 के प्रभाव से लागू पुनरीक्षित वेतनमान (सम्प्रति अपुनरीक्षित) में वेतन प्राप्त करने वाले कर्मियों तथा जिनको 01/01/2005 के प्रभाव से मूल वेतन के 50 प्रतिशत राशि के समतुल्य मंहगाई भत्ता की राशि को मंहगाई वेतन के रूप में लाभ दिया जा चुका है, को दिनांक-01/07/2017 के प्रभाव से मंहगाई भत्ता/राहत की दर 264 प्रतिशत से बढ़ाकर 268 प्रतिशत कर दिया जाय ।

(iii) मंहगाई भत्ता/राहत का भुगतान मूल वेतन/पेंशन एवं महंगाई वेतन/पेंशन के सम्मिलित योग के आधार पर परिगणित किया जायगा, किन्तु विशेष वेतन/वैयक्तिक वेतन पर महंगाई भत्ता अनुमान्य नहीं होगा ।

011117 H0550

(iv) मंहगाई भत्ता/राहत की गणना में 50 पैसे से ऊपर की राशि पूर्ण रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा तथा 50 पैसे कम राशि को छोड़ दिया जायेगा ।

(v) उपर्युक्त महंगाई भत्ता/राहत की राशि का नगद भुगतान किया जायेगा।

5. पेंशन पर महंगाई राहत का भुगतान पुनर्नियोजित पेंशनरों सहित उन पेंशन भोगियों को भी देय होगी जिन्हे क्षतिपूर्ति पेंशन, वार्द्धक्य पेंशन, सेवानिवृति एवं असमर्थता पेंशन प्राप्त है। औपबंधिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं असाधारण पेंशन पाने वाले को भी यह राहत देय होगी।

6. कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबंधिक रूप से कर दिया जायेगा।

7. पेंशनभोगियों को इस महंगाई राहत के भुगतान में विलम्ब के परिहार हेतु बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 206 के अन्तर्गत महालेखाकार, बिहार से बिना प्राधिकार के ही राहत के भुगतान का आदेश राज्य के अन्दर पेंशन लेने वालो के मामले में दिया जाता है। कोषागार पदाधिकारियों को यह भी निदेश दिया जाता है कि बैकों के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने वाले पेशनभोगियों को त्वरित भुगतान कराने के लिए वे सार्वजनिक क्षेत्र के सभी अधिकृत बैकों को इसकी प्रतियाँ भेज दें। बिहार राज्य के बाहर महंगाई राहत की निकासी महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार पत्र पर ही की जा सकती है। महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि राज्य के बाहर पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों से संबंधित महालेखाकारों को अविलम्ब पेंशन राहत भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाय तथा इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाय।

8. उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के कर्मियों/ पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को अपुनरीक्षित वेतनमान में उक्त महंगाई भत्ता/राहत का भुगतान मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद की स्वीकृति से देय होगा।

आदेश– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

ह0/–

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग ।

ज्ञापांक:–3ए-2-वे०पु०(भत्ता)-08/2013- 8398/वि० पटना, दिनांक:-30.10.2017

प्रतिलिपि:–महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग ।

No. 3 A-2-PR-(Allowance) - 08/2013-**8398/Fin.**

GOVERNMENT OF BIHAR

DEPARTMENT OF FINANCE

RESOLUTION

Patna, Dated 25.10.2017

Sub :- Sanction of 268% dearness allowance/relief in the place of 264% w.e.f. 01.07.2017 to State Government Servants/Pensioners/Family Pensioners receiving pay/pension in non revised pay scales as per the Fifth Pay Commission

Vide Department of Finance, Resolution No. 3168 dated 05.052017, sanction had been accorded for dearness allowance/relief at the rate of 256% w.e.f. 01.07.2016 and 264% w.e.f. 01.01.2017 to State Government servants receiving unrevised pay/pension as per the Fifth Pay Commission.

2. Vide Government of India, Ministry of Finance, Department of Expenditure OM No. 1(3)/2008-E-II(B) dated 26/09/2017, sanction has been accorded to revise the pre revised rate of 264% of dearness allowance/relief to Central Government employees receiving un-revised pay/ pension as per the Fifth Pay Commission (i.e. whose pay revision has not been done from 01.01.2016) to 268% w.e.f. 01/07/2017.

3. The State Government also accord sanction of dearness allowance/relief to their employees/ pensioners/family pensioners on the same post and from the same date in accordance with Central Government.

4. In light of the above, the following decisions have been taken after due consideration -

(i) Sanction may be accorded for 268% of dearness allowance/relief w.e.f. 01.07.2017 in the place of 264% in pre revised pay/pension to State Government Servants/Pensioners/Family Pensioners receiving pay/pension in pre revised pay scales as per Fifth Pay Commission.

(ii) Rate of dearness allowance / relief of those employees receiving pay in the revised pay scale (not revised at present) applicable w.e.f. 01.01.1996 and prior to 01.01.2006 and who have been given the benefit of dearness allowance equivalent to 50 percent of the basic pay as dearness pay w.e.f 01.01.2005, may be enhanced from 264% to 268 % w.e.f. 01.07.2017.

(iii) Payment for dearness allowance/ relief will be calculated on the basis of combined sum of pay/ pension and dearness pay/ pension, but dearness allowance shall not be permissible on Special Pay/Personal Pay.

(iv) In the calculation of dearness allowance/ relief 50 paise or more shall be rounded off to next higher rupee and the amount less than 50 paise shall be ignored.

(v) Payment of the amount of above dearness allowance/ relief shall be made in cash.

5. Payment of dearness allowance on pension is admissible to those pensioners also, including re-employed pensioners, who are receiving compensatory pension, old age pension, retirement and disability pension. The relief shall also be payable to those receiving provisional pension/family pension and extraordinary pension.

6. The Treasury Officer shall immediately make provisional payment of relief without waiting for authorization letter from the Accountant General/Finance (Personal Claims Fixation Cell) Department.

7. In order to avoid delay in the payment of dearness relief to pensioners, orders are issued under Rule 206 of Bihar Treasury Code, 2011 for payment of relief without the authorization of the Accountant General, Bihar in the case of pensioners receiving pension within the state. The Treasury/Sub Treasury Officers are also directed to circulate the copies of this order to all authorised Public Sector Banks for making immediate payment to the pensioners receiving payment through banks. Release of dearness relief outside Bihar State shall be made only on the authorisation letter of the Accountant General, Bihar. The Accountant General, Bihar is requested that the Accountants General concerned with the pensioners receiving pension outside Bihar State shall be authorized urgently for the payment of relief on pension under intimation to the Department of Finance.

8. Payment of above dearness allowance/relief on un-revised pay scale to the employees/pensioners/family pensioners of High Court/Bihar Legislative Assembly/ Bihar Legislative Council shall be made with the sanction of the Chief Justice, High Court, Patna/ Chairman, Bihar Legislative Assembly/Speaker, Bihar Legislative Council.

ORDER - **It is ordered that this Resolution be published in the next edition of the Gazette of Bihar for the information of general public.**

Sd/-
(Rahul Singh)
Secretary (Expenditure), Dept. of Finance

Endt No. 3A-2-PR-(Allowance)-08/2013-**8398-Fin.** Patna, Dated:- **30.10.2017**

Copy to:- The Accountant General (A&E), Bihar, Birchand Patel Marg, Patna, for information and necessary action.

Sd/-
(Rahul Singh)
Secretary (Expenditure), Dept. of Finance